<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>15/09/2025</u>

श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में आयोजित प्रवर्तन निदेशालय के आंचलिक अधिकारियों (क्यूसीजेडओ) का 32वां त्रैमासिक सम्मेलन

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 12 और 13 सितंबर 2025 को श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में आंचलिक अधिकारियों (क्यूसीजेडओ) के अपने 32वें त्रैमासिक सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस दो दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय ने की और इसमें सभी विशेष निदेशकों, अपर निदेशकों, संयुक्त निदेशकों और उप/सहायक कानूनी सलाहकारों ने भाग लिया।

श्रीनगर में सम्मेलन आयोजित करने का यह निर्णय मुख्य रूप से कुछ महीने पहले पहलगाम में दुर्भाग्यपूर्ण आतंकवादी हमले के बाद राज्य की सुरक्षा व्यवस्था में विश्वास बहाल करने के लिए लिया गया था। सम्मेलन के सफल समापन से यह परिलक्षित हुआ कि जम्मू और कश्मीर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विचार-विमर्श के लिए एक सुरक्षित, जीवंत और दूरदर्शी स्थल बना हुआ है।

3. सम्मेलन के दौरान जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें से एक पीएमएलए मामलों की सुनवाई में तेज़ी लाने से संबंधित था। ईडी निदेशक ने आँकड़ों की समीक्षा की और क्षेत्रीय प्रमुखों को लंबित जाँचों में तेज़ी लाने, अंतिम अभियोजन शिकायतों को दर्ज करना सुनिश्चित करने और मुकदमों में तेज़ी लाने के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्देश दिया। पीएमएलए के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने संबंधी *विजय मदनलाल चौधरी* के फैसले की समीक्षा के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पीठ की टिप्पणियों के बाद, यह ध्यान दिया गया कि विशेष पीएमएलए अदालतें स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सभी मुख्य न्यायाधीशों के रजिस्ट्रारों को पत्र भेजे गए थे।

4. यद्यपि, चर्चा में यह भी उल्लेख किया गया कि पीएमएलए अभियोजन विधेय अपराध की वृद्धि से जुड़े हुए हैं, और उन मामलों में देरी या प्रतिकूल परिणाम पीएमएलए परीक्षणों को प्रभावित करते हैं। बहरहाल, यह ध्यान दिया गया कि विशेष न्यायालयों द्वारा योग्यता के आधार पर तय किए गए मामलों में, एजेंसी ने वास्तव में 53 में से 50 मामलों में दोषसिद्धि सुनिश्चित की है, जिसकी दोषसिद्धि दर 94 प्रतिशत से अधिक है, जो भारत और विश्व स्तर पर सभी एजेंसियों में सबसे अधिक हो सकती

है। इसके अलावा, यह भी स्वीकार किया गया कि ईडी पीड़ितों और वैध दावेदारों को 34,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति सफलतापूर्वक वापस दिलाने में भी सक्षम रही है।

5. सम्मेलन के दौरान चर्चा किये गए अन्य महत्वपूर्ण विषय निम्नलिखित हैं:

- **मामला प्रबंधन डेटाबेस की समीक्षा:** ईडी की आंतरिक मामला प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा की गई और एक महीने के भीतर डेटा प्रविष्टि को पूरा करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। मुख्यालय को निर्देश दिया गया कि यदि आवश्यक हो तो अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया जाए।
- **पुष्टिकृत कुर्क संपत्तियों का कब्जा:** *विजय मदनलाल चौधरी* मामले में फैसले के बाद पीएमएलए के तहत कुर्क की गई संपत्तियों पर कब्ज़ा लेने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की गई और असाधारण मामलों की परिभाषा में अस्पष्टता पर ध्यान दिया गया। ईडी अपराधियों को अपराध का फल भोगने से रोकने के लिए जहाँ भी संभव हो, कब्ज़ा लेने का प्रयास कर रहा है, जबकि संशोधित नियमों पर काम चल रहा है।
- **परिसंपत्ति वसूली और प्रबंधन:** संपत्तियों के मूल्यांकन, कब्जे और निपटान में चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए, मौजूदा दिशानिर्देशों में संशोधन, पारदर्शी नीलामी के लिए बांकनेट BAANKNET प्लेटफॉर्म को अपनाने, और एक समर्पित परिसंपत्ति प्रबंधन इकाई और परिसंपत्ति वसूली कोष की स्थापना की संभावना सहित सुधारों पर विचार-विमर्श किया गया। **आईबीसी और पीएमएलए इंटरफेस:** आईबीबीआई के साथ समन्वित दिशानिर्देशों और एनसीएलटी के पुराने मामलों के समाधान के माध्यम से दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) और पीएमएलए के बीच विवादों को सुलझाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। इस बात पर भी चर्चा की गई कि जिन मामलों में आईबीसी के प्रावधानों का दुरुपयोग किया जा रहा है, उनकी पहचान की जा सकती है।
- **फेमा और फेरा मामले:** यह आग्रह किया गया कि फेमा जांच को अधिक गंभीरता से लिया जाए तथा पुराने फेरा न्यायिक मामलों को बिना किसी देरी के बंद करने पर भी बल दिया गया।

- **साइबर और डिजिटल धोखाधड़ी:** सम्मेलन के मद से कई क्षेत्रों में चल रहे बड़े मामलों की जांच की पुष्टि हुई और यह निर्णय लिया गया कि जांच पद्धतियों और केस संकलन को व्यवस्थित रूप से समेकित किया जाए।
- **ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग:** प्रतिबंध के बाद अवैध प्लेटफार्मों की आगामी चुनौती की ओर ध्यान आकर्षित किया गया तथा इससे निपटने के लिए केंद्रित रणनीति बनाने का आह्वान किया गया।
- **परिचालन सुधार:** परिपत्रों और मैनुअलों में संशोधन की आवश्यकता के साथ-साथ केस प्रबंधन को अधिक मजबूत प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित करने और ई-ऑफिस प्रणाली के अधिक उपयोग पर चर्चा की गई।
- **निवारक सतर्कता:** सभी वरिष्ठ अधिकारियों को निवारक सतर्कता बनाए रखने और ईमानदारी, जवाबदेही, प्रतिबद्धता और उत्कृष्टता के ईडी के मुख्य मूल्यों की पुष्टि करने के लिए जागरूक किया गया।

  सभी वरिष्ठ अधिकारियों को निवारक सतर्कता बनाए रखने तथा ईडी के मूल मूल्यों, ईमानदारी, जवाबदेही, प्रतिबद्धता और उत्कृष्टता की पुष्टि करने के लिए जागरूक किया गया।
- **प्रत्याहरण लक्ष्य:** पीड़ितों को धन वापसी (प्रत्याहरण) करने के महत्व पर जोर देते हुए, ईडी के अन्वेषण प्रयासों के बाद सहारा से संबंधित मामले में धन वापसी में पर्याप्त वृद्धि को देखते हुए, इस वित्त वर्ष में ₹15,000 करोड़ की धन वापसी करने के लक्ष्य पर जोर दिया गया।

6. अंत में, प्रशासनिक मामलों पर चर्चा करते हुए, यह ध्यान दिया गया कि ईडी ने प्रमुख अधिग्रहणों और स्वीकृतियों के साथ अपने बुनियादी ढाँचे को काफ़ी मज़बूत किया है, जिसमें एकीकृत परिसर के लिए बीकेसी मुंबई में ज़मीन, भुवनेश्वर, पटना और रायपुर में नए आंचलिक कार्यालय, कोलकाता कार्यालय का नवीनीकरण और जालंधर, देहरादून, शिलांग, कोच्चि, अहमदाबाद और चंडीगढ़ में नए कार्यालय के लिए जगह हासिल करना शामिल है।

इस बात पर भी चर्चा हुई कि अगले तीन से चार वर्षों के भीतर, ईडी अपने सभी कार्यालय स्वयं के स्वामित्व वाले परिसरों में स्थापित करने का प्रयास करेगा।

7. सम्मेलन का समापन अंतर-क्षेत्रीय समन्वय को मजबूत करने, दूरदर्शी कार्रवाई बिंदुओं तथा धन शोधन, विदेशी मुद्रा उल्लंघनों और अन्य आर्थिक अपराधों के विरुद्ध वैधानिक ढांचे को बनाए रखने की प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि के साथ हुआ।